राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

योजना विभाग

चौथा स्तर, बी- विंग , दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली – 110002

अतारांकित प्रश्न संख्या- 45

दिनांक- गुरुवार, ७ जून २०१८

प्रश्नकर्ता का नाम - श्री ओमप्रकाश

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि उप मुख्यमंत्री ने इस वर्ष अपना आउटकम बजट पेश करते हुए यह वायदा किया था की विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हर कार्य को पूरा किया जाने की टाइम लाइन निर्धारित कर रही है ?	बजट भाषण के भाग - ग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की यह घोषणा की गई थी।
ख) दिल्ली सरकार द्वारा किस किस योजना के कार्यान्वन के लिए टाइम लाइन निर्धारित की गई है ?	भाग-ग के अंतर्गत ६ विभागों की कुल ११ योजनायें है, जिसकी सूची संलग्न है।
शिक्षा विभाग से प्राप्त सुचना के अनुसार	
ग) अब तक किन किन योजनाओं के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पाई है ?	लागू नहीं।
घ) टाइम लाइन के कियांन्विन में असफल होने के क्या कारण रहे? ; और	इस योजना (Installation of 1.2 lakh CCTV Cameras in all Govt. school buildings) के पूर्वत: DSIIDC द्वारा क्रियान्वित किया जाना था परन्तु माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के दिनांक ०६.०४.२०१८ के निर्देशानुसार अब इस योजना को PWD क्रियान्वित करेगा। जिस कारण इस योजना के क्रियान्वन के लिए टाइम लाइन बदलाव की आवश्यकता है। इस योजना के टाइम लाइन को पुन: निर्धारण करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इस योजना का क्रियान्वन वर्ष २०१८-१९ में पूर्ण होने की संभावना है, जैसा की बजट स्पीच में कहा गया है।
ङ.) इसका योजनाओं के क्रियान्वन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?	उपरोक्त
स्वास्थय विभाग से प्राप्त सुचना के अनुसार	
ग) अब तक किन किन योजनाओं के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पाई है ?	यूनिवर्सल हैल्थ केयर इन्सुरेंस स्कीम, आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास (Development of Hospital Information management system) तथा डाक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को उनके व्यावसायिक विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजने की योजना के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पाई है।

प्रश्न	उत्तर
घ) टाइम लाइन के कियान्विन में असफल होने के क्या कारण रहे? ; और	यूनिवर्सल हैल्थ केयर इन्शुरन्स स्कीम- एम्पॉवर्ड समिति ने अभी आर एफ पी को अंतिम रूप नहीं दिया है। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक- (1) भूमि स्वामी विभाग (Land Owning Agencies) जैसे दिल्ली जल बोर्ड, डी डी ए., पी. डब्लू. डी. आदि द्वारा भूमि को अस्थायी रूप से स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने में विलम्ब। (2) मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को एम्पैनलमेंट की जा रही है। (3) मोहल्ला क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाले टेबलेट की स्पेसिफिकेशन के पूरा होने में आई. टी. विभाग द्वारा विलम्ब। अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास योजना- इसके लिए ड्राफ्ट निविदा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को उनके व्यवसायिक विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजना - इस योजना के विभिन्न विवरणों के लिए विशेषज्ञों की बहुअनुशासनात्मक / बहुआयामी समिति / उप-समिति का गठन अभी तक गठित किया जाना है
ङ.) इसका योजनाओं के क्रियान्वन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?	उपरोक्त कारणों से योजना के क्रियान्वन में निर्धारित टाइम लाइन से थोड़ा अधिक समय लग सकता है किन्तु स्वास्थ्य विभाग इसे समय रहते पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है।
दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त सुचना के अनुसार	
ग) अब तक किन किन योजनाओं के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पाई है ?	विकेन्द्रीकृत अवजल शोधन संयंत्र परियोजनाएं तथा बल्क फ्लोमीटर लगाने की परियोजना को पूरी करने का निर्धारित समय- सीमा अभी शेष है
घ) टाइम लाइन के कियान्विन में असफल होने के क्या कारण रहे? ; और	भाग ग के उत्तर के सन्दर्भ में लागू नहीं
ङ.) इसका योजनाओं के क्रियान्वन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?	
प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त सुचना के अनुसार	
ग) अब तक किन किन योजनाओं के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पाई है ?	"डोर-स्टेप" डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज" प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय से एक माह पीछे है जिसके पीछे टैंडर डॉक्यूमैंट का मूल्यांकन में लगा अधिक समय का, टाइमलाइन निर्धारित करते समय सही आंकलन न कर पाना था एवं मूल्यांकन समिति की 'प्री-क्वालिफिकेशन रिपोर्ट' को फाइनेंस व लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन जानने का प्रावधान टाइमलाइन में नहीं किया गया था जोकि कमेटी रिपोर्ट अनुसार आवश्यक था। कृपया क्रियान्वित कार्य की टाइमलाइन 'परिशिष्ट-अ' पर देखें।
घ) टाइम लाइन के कियान्विन में असफल होने के क्या कारण रहे? ; और	
ङ.) इसका योजनाओं के क्रियान्वन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?	यह योजना निर्धारित समय से लगभग एक माह की देरी से लागू हो पाएगी।

प्रश्न	उत्तर
परिवहन विभाग से प्राप्त सुचना के अनुसार	
ग) अब तक किन किन योजनाओं के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पाई है ?	विभाग की निम्न योजनाओं के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पायी हैं :- 1. 1000 पूर्णतया इलेक्ट्रिक बसों की खरीददारी कारण : केबिनेट नोट के मसोदे मे शुद्धिकरण एवं माननीय परिवहन मंत्री द्वारा आदेशित अतिरिक्त जानकारी डिम्ट्स (DIMTS) के सलाहकार से प्राप्त करने मे समय लगने के कारण इस योजना मे विलम्ब हुआ हैं। 2. 1000 क्लस्टर बसों को क्लस्टर योजना मे जोड़ना कारण : कार्यालय की प्रक्रिया एवं इस मामले का उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के अधीन होने के कारण 3. दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े मे 1000 स्टैण्डर्ड फ्लोर बसे लाने हेतु। कारण : वर्तमान मे कार्य समयानुसार चल रहा हैं।
घ) टाइम लाइन के कियोन्विन में असफल होने के क्या कारण रहे? ; और	उपरोक्तानुसार
ङ.) इसका योजनाओं के क्रियान्वन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?	समय अवधि मे वृद्धि हो सकती हैं
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	
ग) अब तक किन किन योजनाओं के लिए टाइम लाइन क्रियान्वित नहीं हो पाई है ?	राशन की घर द्वार वितरण योजना।
घ) टाइम लाइन के कियोन्विन में असफल होने के क्या कारण रहे? ; और	राशन की घर द्वार वितरण की योजना को केबिनेट द्वारा आदेश सं०-२५६१ दिनांक ०६.०३.२०१८ को मंजूरी दी गई है जो सरकार के अनुमोदन हेतु लंबित है।
ङ.) इसका योजनाओं के क्रियान्वन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?	प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् ही क्रियान्वन की समय सीमा आबद्ध होगी, तत्पश्चात इसके प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।

योजनाओं की सूची

SECTION C: PROJECTS WITH SPECIFIC TIMELINES

DIRECTORATE OF EDUCATION

1 "Installation of 1.2 lakh CCTV in all govt. school buildings

HEALTH

1 "Implementation of Universal Healthcare in Delhi

2 "Aam Aadmi Mohalla Clinic

3 "Implementation of Hospital Information Management System

TRANSPORT

1 To roll out 1000 fully-electric buses

2 To start the work to induct 1000 standard size buses in DTC fleet.

3 About 1000 new cluster buses to be added under cluster scheme.

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

1 "Door Step Delivery of Public Services

DELHI JAL BOARD (WATER SUPPLY)

1 "Metering and Leakage Management

2 "Sewerage facilities in Unauthorised Colonies

FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

1 DOOR STEP DELIVERY OF RATION

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

परिशिष्ट – अ

Sl. No.	Milestone	Time-line	Status as on 29/05/2018
1	2	3	4
1.	Floating of eTender	01.03.2018 (with effect from 02.03.2018)	Done
2.	Pre-Bid Meeting	08.03.2018 (Concluded)	Done
3.	Response to queries	14.03.2014	Done
4.	Last date of submission of bid	23.03.2018 upto 02.00pm	Done
5.	Opening of eTender	23.03.2018 at 03.00pm	Done
6.	Scrutiny of documents submitted in relation to Pre-qualification	03.04.2018 (05 working days) -Depends on number of bids and their reply to various queries sought by the Committee	Done
7.	Presentation on the Project	06.04.2018 (03 days notice to bidder)	Done
8.	Opening of Technical Bid	10.04.2018 (One working day)	Done
9.	Scrutiny of documents submitted in relation to Technical – Qualification and awarding marks by the committee	17.04.2018 (05 working days) - Depends on the number of bids and their reply to various queries sought by the Committee before awarding the marks.	Done
10	Opening of financial bid and recommending the successful bidder by the Committee	19.04.2018	Done (On 23.05.2018)
11	Approval of recommendation of the Committee by the Hon'ble Minister	20.04.2018	Approved on 28.05.2018
12	Approval by the Finance Department	25.04.2018	Sent to Finance Department for Expenditure Sanction on 29.05.2018
13	Vetting of the draft agreement by the Law Department	27.04.2018	Sent to Law Department on 31.05.2018
14	**Signing of agreement with the successful bidder**	**01.05.2018**	
15	**Launching of the project**	**15.06.2018 (T+6 weeks as per RFP)**	

VFS Global Services Private Limited has been selected as the Intermediary agency for the project with the approval of Hon'ble Minister AR. Agreement to be signed with the company has been sent to Law Department on 31.05.2018. Upon receipt of Expenditure Sanction from Finance Department, agreement is likely to be signed with the company within a week. The project "Doorstep Delivery of Public Services" will be launched within 06 weeks there from as per the terms of the RFP.